

अनुच्छेद 370: सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को समझना

यह एडिटरियल 12/12/2023 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित ["Today, a clean canvas for every child in J&K"](#) लेख पर आधारित है। इसमें विविधता की गई है कि धारा 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का हाल का नरिणय ऐतहासिकि एवं युगांतकारी नरिणय है जो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता और जम्मू-कश्मीर के लोगों की इच्छा को संपुष्ट करता है।

प्रलिस के लयि:

[अनुच्छेद 370](#) और [35A](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#), [वशिष दरजा](#), [जम्मू और कश्मीर पुनरगठन अधनियम, 2019](#), [एसआर बोमई बनाम भारत संघ, 1994](#), [प्रधान मंत्री वकिस पैकेज \(PMDP\)](#), [औद्योगिकि वकिस योजना \(IDS\)](#)।

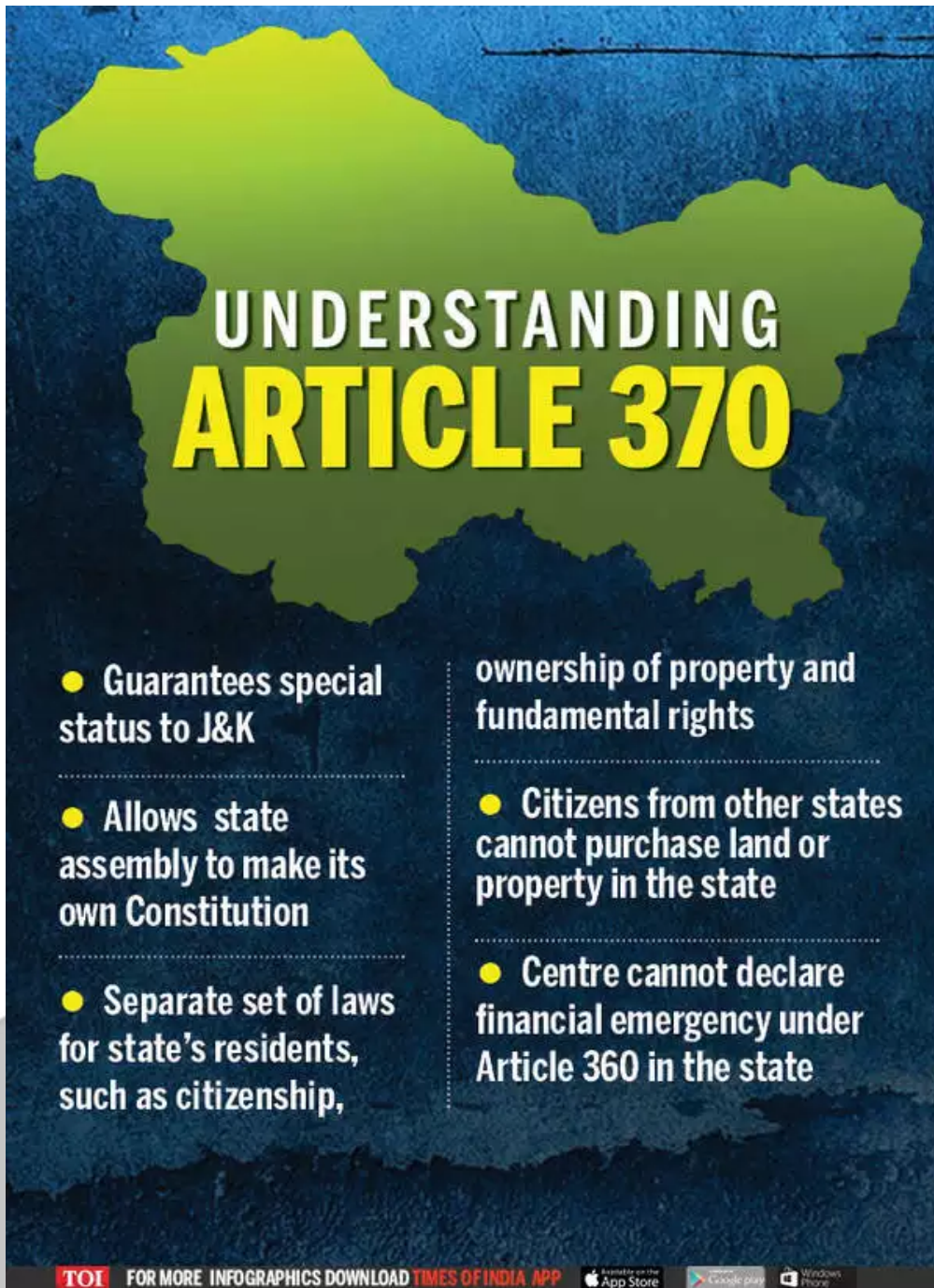
मेन्स के लयि:

अनुच्छेद 370, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, धारा 370 को हटाने के पीछे के कारण, धारा 370 को हटाने का प्रभाव।

11 दसिंबर 2023 को [भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय](#) ने [अनुच्छेद 370 और 35A](#) के नरिसुतीकरण पर अपना ऐतहासिकि नरिणय सुनाया। इस नरिणय के माध्यम से [न्यायालय](#) ने [भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की संपुष्टकी](#), जसि प्रत्येक भारतीय अपने मन में संजोकर रखता है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को नरिसुत करने का सरकार का नरिणय—जसिने तत्कालीन जम्मू-कश्मीर [राज्य के वशिष दरजा](#) को समाप्त कर दिया—संवैधानिकि एकीकरण को बढ़ावा देने के लयि लयिा गया था न कि वधितन के लयि। न्यायालय ने इस तथ्य को भी सुवीकार कयिा कि [अनुच्छेद 370](#) अपनी प्रकृति में 'अस्थायी' (temporary) था।

अनुच्छेद 370:

- भारतीय संवधान में अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को वशिष दरजा प्रदान करता था जो भारत, पाकसुतान और चीन के मध्य एक वविादति क्षेत्त्र है।
 - इसका मसौदा भारतीय [संवधान सभा](#) के सदस्य एन. गोपालसुवामी आयंगर ने तैयार कयिा था थे और इसे वर्ष 1949 में 'अस्थायी उपबंध' (temporary provision) के रूप में संवधान में जोड़ा गया था।
- इसने राज्य को अपना संवधान एवं ध्वज रखने के साथ ही रकषा, वदिशी मामले एवं संचार को छोड़कर अधकिंश मामलों में सुवायतुता रखने की अनुमती दी।
- यह वलिय पत्त्र (Instrument of Accession) की शर्तों पर आधारति था, जसि पर वर्ष 1947 में पाकसुतान के आक्रमण के बाद भारत में शामिल होने के लयि जम्मू-कश्मीर के शासक हरसिहि ने हसुताकषर कयिे थे।



सरकार ने अनुच्छेद 370 को किस प्रकार नरिस्त किया?

- **राष्ट्रपति का आदेश (Presidential Order):** वर्ष 2019 के राष्ट्रपति के आदेश में संसद ने एक प्रावधान पेश करते हुए 'जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा' को 'जम्मू और कश्मीर की विधान सभा' के रूप में नया अर्थ प्रदान किया और फरि अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए **राष्ट्रपति शासन** के माध्यम से विधान सभा की शक्तियों को ग्रहण कर लिया।
- **संसद में संकल्प:** संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा क्रमशः 5 और 6 अगस्त 2019 को समवर्ती संकल्प पारित किये गए। इन संकल्पों ने अनुच्छेद 370 के शेष प्रावधानों को भी रद्द कर दिया और उन्हें नए प्रावधानों से प्रतिस्थापित किया।
- **जम्मू और कश्मीर पुनर्रगठन अधिनियम:** **जम्मू और कश्मीर पुनर्रगठन अधिनियम 2019** को संसद द्वारा 5 अगस्त 2019 को पारित किया गया। इस अधिनियम ने जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों- 'जम्मू और कश्मीर' तथा 'लद्दाख' में विभाजित कर दिया।



सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा?

- अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान: न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और जम्मू-कश्मीर राज्य की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी।
 - न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 दो प्राथमिक कारणों से एक 'अस्थायी प्रावधान' था।
 - इसने एक संक्रमणकालीन उद्देश्य की पूर्ति की, जो थी जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की स्थापना के लिये एक अंतरिम व्यवस्था करना, जसि राज्य संविधान का मसौदा तैयार करना था।
 - इसका उद्देश्य वर्ष 1947 में राज्य में व्याप्त युद्ध जैसी स्थितिके मद्देनजर जम्मू-कश्मीर के भारत संघ में एकीकरण को आसान बनाना था।
- राज्यपाल राज्य विधानमंडल की 'सभी या कोई भी' (all or any) भूमिका ग्रहण कर सकता है: न्यायालय ने [\[2023\] 2023 \(1994\)](#) मामले के ऐतिहासिक नरिणय (जो राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यपाल की शक्तियों एवं सीमाओं से संबंधित है) का हवाला देते हुए यह माना राज्यपाल राज्य विधानमंडल की 'सभी या कोई भी' (all or any) भूमिका ग्रहण कर सकता है।
 - भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि राज्यपाल (जम्मू-कश्मीर के मामले में राष्ट्रपति) राज्य विधानमंडल की 'सभी या कोई भी' भूमिका नभिया सकता है और ऐसी कार्रवाई का न्यायिक परीक्षण केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिये।
- राज्य सरकार की सहमति आवश्यक नहीं: न्यायालय ने अपने नरिणय में कहा कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकपक्षीय रूप से अधिसूचित कर सकता है कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है।
 - इसमें आगे कहा गया कि राष्ट्रपति को इस संबंध में राज्य सरकार की सहमति (concurrency) प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि अनुच्छेद 370(1)(d) के परंतुक द्वारा नरिदष्ट है।
- वर्ष 2019 के कानून की संपुष्टि: न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की उस सीमा तक संपुष्टि की जहाँ तक जम्मू-कश्मीर राज्य से केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख को पृथक किया गया।
 - न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रस्तावित पुनर्गठन के संबंध में राज्य विधानमंडल के विचार अनुशासनात्मक प्रकृति के हैं और संसद पर बाध्यकारी नहीं हैं।
- राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद महज विधि निरिमात्री संस्था नहीं: मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के तहत किसी राज्य में संसद की शक्ति महज विधि निरिमाण तक ही सीमित नहीं है। इसका वसितार कार्यकारी कार्रवाई तक भी होता है।
 - न्यायालय ने यह भी कहा कि जब अनुच्छेद 356 के तहत कोई उद्घोषणा प्रवर्तन में होती है तब ऐसे कई नरिणय होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा दनि-प्रतदिनि के प्रशासन के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से लिये जाते हैं।
 - राज्य की ओर से केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा लिया गया प्रत्येक नरिणय और कार्रवाई चुनौती के अधीन नहीं है।
 - प्रत्येक नरिणय को खुली चुनौती देने से अराजकता और अनश्चितता की स्थिति उत्पन्न होगी।
- चुनाव कराने के साथ राज्य का दर्जा बहाल करना: न्यायालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिये। उसने आदेश दिया कि जम्मू-कश्मीर की विधान सभा के चुनाव 30 सितंबर 2024 तक संपन्न करा लिये जाएँ।

- 'सत्य और सुलह आयोग' की स्थापना: न्यायमूर्त कौल ने अपने सहमत राय (concurring opinion) में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के बाद स्थापित आयोग की तरह पर एक 'सत्य और सुलह आयोग' (Truth and Reconciliation Commission) की स्थापना का प्रस्ताव किया ताकि 1980 के दशक से जम्मू-कश्मीर में राज्य और गैर-राज्य अभिक्रिता दोनों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन को संबोधित किया जा सके।

ART 370 FOR INTEGRATION, NOT DISINTEGRATION: SC

WHAT ART 370 SAYS ABOUT SCRAPPING PROVISIONS

Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the **President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative...**

Provided that the **recommendation of the Constituent Assembly of the State... shall be necessary** before the President issues such a notification

➤ Petitioners said that since J&K constituent assembly had ceased to exist, **Art 370 became a permanent feature**

➤ SC says '**President had the power to issue a notification declaring that Article 370(3) ceases to operate without the recommendation of the constituent assembly**'. Also says '**President did not have to secure the concurrence of the state govt or Union govt acting on behalf of the state govt**

WHAT SC JUDGMENT SAYS

① Erstwhile J&K state **did not have internal sovereignty different from other states** of the country after it became part of India

② '**Exercise of presidential power to issue constitutional order abrogating Article 370 of Constitution is valid**

③ **Constituent assembly of J&K was never intended to be a permanent body**; Article 370 was a temporary provision

④ **Creation of the UT of Ladakh upheld**; not necessary to look into the same for UT of Jammu & Kashmir since it is temporary

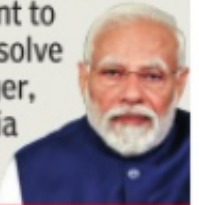
⑤ EC to conduct **elections to J&K legislative assembly by Sept 30, 2024**. 'Restoration of statehood shall take place at the earliest

➤ Bench pronounced **3 separate and concurring judgments**

➤ Justice S K Kaul sought '**impartial truth & reconciliation**' panel to probe human rights violations by state and non-state actors

“ It is a resounding declaration of hope, progress and unity for our sisters and brothers in Jammu, Kashmir and Ladakh... (It is) a testament to the collective resolve to build a stronger, more united India

— PM MODI



PM's article in TOI | P 12

“ Full statehood must be restored immediately... we believe elections should be held immediately, there is no reason to wait till September 2024 — CONGRESS

“ It is nothing less than a death sentence not only for J&K, but for the idea of India — MEHBOOBA MUFTI | PDP

“ (Quoting Faiz) My heart is helpless, but not hopeless, the evening of sorrow is long, but it's just an evening — OMAR ABDULLAH | NC

अनुच्छेद 370 क्यों हटाया गया?

- **एकीकरण और विकास:** अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर के भारतीय संघ में पूर्ण एकीकरण में बाधा डाली, अलगाववाद की भावना पैदा की और राज्य के विकास को बाधित किया।
 - यह माना जा रहा था कि पूर्ण एकीकरण से जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिये संसाधनों, अवसरों और अवसरों तक बेहतर पहुँच की स्थिति बनेगी।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** क्षेत्र में आतंकवाद और अलगाववाद का समर्थन करने के लिये पाकिस्तान द्वारा अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग किया जा रहा था। इसे नरिस्त करने से भारत सरकार के इस क्षेत्र पर अधिक नियंत्रण होने और आतंकवादी गतिविधियों पर नकेल कसने के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ होगी।
- **भेदभाव समाप्त करना:** अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर में महिलाओं, दलितों और हाशिये पर स्थिति अन्य समूहों के वरिद्ध भेदभाव करता था। इसे नरिस्त करने से ये समूह भारतीय कानूनों के दायरे में आ जाएँगे और उन्हें समान अधिकार एवं अवसर प्राप्त होंगे।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर के शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी पैदा की। इसके नरिसन से राज्य **केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)** और **सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI)** के दायरे में आ जाएगा, जिससे बेहतर प्रशासन एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
- **आर्थिक समृद्धि:** अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर में आर्थिक विकास को बाधित किया। इसे नरिस्त करने से क्षेत्र में अधिक निवेश, पर्यटन और रोजगार सृजन की अनुमति मिलेगी।

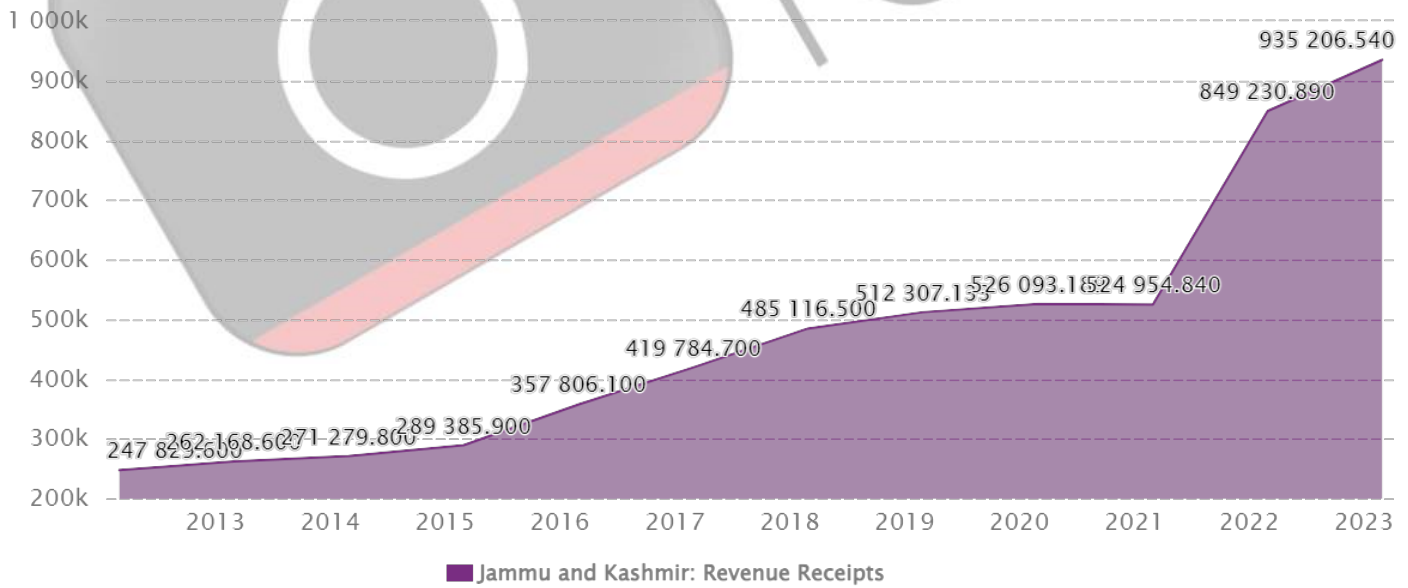
अनुच्छेद 370 के नरिसन का प्रभाव:

- **हिसा में गरिबट:** अनुच्छेद 370 के नरिसन के बाद से जम्मू-कश्मीर में हिसा की घटनाओं में उल्लेखनीय गरिबट आई है।
 - आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, पछिले चार वर्षों में आतंकवादी घटनाओं की संख्या में 50% से अधिक की कमी आई है और सुरक्षा बलों ने 300 से अधिक आतंकवादियों को मार गरियाा है।
 - इसका श्रेय कई कारकों के संयोजन को दिया जा सकता है, जनिमें सुरक्षा उपायों की वृद्धि, खुफिया सूचनाओं का बेहतर संग्रहण और उग्रवाद के लिये सार्वजनिक समर्थन में गरिबट शामिल हैं।

FEWER INJURIES, DEATHS AMONG SECURITY FORCES

Incidents	52 months before Aug 5, 2019	52 months after Aug 5, 2019
Terrorist-initiated incidents	765	455
Attacks on civilians	193	156
Civilian casualties	234	131
Civilians injured	1,300	422
Encounters	390	338
Security forces injured	1,098	334
Security forces killed	355	125

- **बेहतर आर्थिक विकास:** सरकार ने जम्मू-कश्मीर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये कई पहलें लागू की हैं, जैसे प्रधानमंत्री विकास पैकेज (PMDP) और औद्योगिक विकास योजना (IDS)।
 - इन पहलों से क्षेत्र में निवेश, रोज़गार सृजन और आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है।
 - केंद्रशासित प्रदेश के रूप में जम्मू-कश्मीर में कर राजस्व में 31% की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2022-23 के दौरान जम्मू-कश्मीर की GDP स्थिति कीमतों पर 8% की दर से बढ़ी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 7% रही।



SOURCE: WWW.CEICDATA.COM | Reserve Bank of India

- **उन्नत अवसंरचना:** सरकार ने जम्मू-कश्मीर में अवसंरचना क्षेत्र के विकास में भी भारी नविश किया है। इसमें नई सड़कों, पुलों, सुरंगों और बजिली लाइनों के निर्माण जैसी परियोजनाएँ शामिल हैं।
 - इन सुधारों ने लोगों के लिये क्षेत्र में यात्रा करना और व्यापार करना आसान बना दिया है।
- **पर्यटन में वृद्धि:** अनुच्छेद 370 के नरिस्त होने के बाद से **जम्मू-कश्मीर आने वाले पर्यटकों की संख्या में व्यापक वृद्धि हुई है।** बेहतर सुरक्षा, बेहतर वणिणन और नई पर्यटन पहलों की शुरुआत सहति वभिन्न कारकों के संयोजन से यह संभव हुआ है।
 - एक रपिर्त के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में **वर्ष 2022 में 1.62 करोड पर्यटक आए, जो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों में सर्वाधिक है।**

नषिकर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय के हाल के नरिणय ने न केवल 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के सिद्धांतों को संपुष्ट किया है, बल्कि इसने सुशासन के लिये एकता एवं सामूहिक समर्पण के महत्त्व को भी सिद्ध किया है। इस नरिणय ने हमारे राष्ट्र के ताने-बाने को सुदृढ़ करने और एक समाज के रूप में हमें परभिषति करने वाले मूल्यों को प्रबल करने में न्यायालय की प्रतबिद्धता को भी प्रकट किया है।

अभ्यास प्रश्न: अनुच्छेद 370 को नरिस्त करने के वषिय पर सर्वोच्च न्यायालय के हाल के नरिणय की वविचना कीजिये और इस क्षेत्र में हसिा के साथ आर्थिक विकास, अवसंरचनात्मक विकास और पर्यटन पर इस नरिणय के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

????????

प्रश्न. सयिाचनि ग्लेशयिर स्थति है: (2020)

- अकसाई चनि के पूर्व में
- लेह के पूर्व में
- गलिगति के उत्तर में
- नुबरा घाटी के उत्तर में

उत्तर: (d)

??????

प्रश्न. भारतीय संवधान का अनुच्छेद 370, जसिके साथ हाशयिा नोट " जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध" लगा हुआ है, कसि सीमा तक अस्थायी है? भारतीय राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबंध की भावी संभावनाओं पर चर्चा कीजिये? (2016)

प्रश्न. आंतरिक सुरक्षा खतरों तथा नरिंतरण रेखा सहति म्याँमार, बांग्लादेश और पाकस्तान सीमाओं पर सीमा-पार अपराधों का वशिलेषण कीजिये। वभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा नभिाई गई भूमिका की वविचना भी कीजिये। (2020)

प्रश्न. जम्मू और कश्मीर में 'जमात ए इस्लामी' पर पाबंदी लगाने से आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं (ओ-जी-डब्ल्यू) की भूमिका ध्यान का केंद्र बन गई है। उपप्लव (बगावत) प्रभावति क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं द्वारा नभिाई जा रही भूमिका का परीक्षण कीजिये। भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं के प्रभाव को नषिप्रभावति करने के उपायों की चर्चा कीजिये। (2019)